

**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्यात 3197**  
**16 मार्च, 2015 को उत्तर के लिए**

**इस्पात क्षेत्र का कार्यनिष्पादन**

3197. श्री भोला सिंह:

श्री अनिल शिरोले:

श्री आर. गोपालकृष्णन:

श्री विजय कुमार हांसदाक:

श्रीमती पूनम महाजन:

श्री प्रताप सिम्हा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में परिचालन कर रहे सरकारी और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है और इनकी वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार से निरंतर सहायता के बावजूद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहित सरकारी क्षेत्र के कतिपय इस्पात संयंत्र गत तीन वर्ष के दौरान घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए नई राष्ट्रीय इस्पात नीति में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में इस्पात क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने और इसके विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**इस्पात और खान राज्य मंत्री**

**श्री विष्णु देव साय**

(क): सार्वजनिक क्षेत्र में 9 इस्पात संयंत्र और निजी क्षेत्र में 1321 इस्पात संयंत्र मौजूद हैं । संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर देश में प्रमुख इस्पात संयंत्रों की शुद्ध लाभ/हानि नीचे दी गई है :-

कंपनी	शुद्ध लाभ/हानि (रूपये करोड़ में)		
	2011-12	2012-13	2013-14
सेल	3542.72	2170.35	2616.48
आरआईएनएल	751.00	353.00	366.00
टाटा स्टील लिमिटेड	6696.40	5062.97	6,412.19
जेएसडब्ल्यू, 4 सी	1625.86	1801.22	1334.51
जेएसडब्ल्यू, 4 ए स्पाक स्टील	(316.92)	85.81	-
जेएसपीएल (स्टील एलोन)	2110.65	1,592.55	1291.95
एस्साइरस्टील	(1,251)	(2785)	N.A.
स्रोत: कंपनी का तुलनपत्र; ^ वर्ष 2012-13 से जेएसडब्ल्यू के स्टील का भाग (कोष्ठक) के अंतर्गत आंकड़े शुद्ध हानि दर्शाते हैं।			

(ख) और (ग) : गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के दो इस्पात संयंत्रों अर्थात् सेल और आरआईएनएल/वीएसपी का वित्तीय निष्पादन जैसे कि उपर दर्शाया गया है, यह दर्शाता है कि दोनों संयंत्रों ने इस अवधि के दौरान शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

(घ): राष्ट्रीय इस्पाकत नीति 2005 के अनुसार वर्ष 2019-20 तक इस्पात का उत्पादन 110 एमटी प्रक्षेपित किया गया है।

(ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त उद्योग होने के नाते सरकार की भूमिका एक सुविधादाता मात्र के रूप में सीमित है।

\*\*\*